year? If he can tell us the years to which these profits relate, Sir, it will be perhaps shocking. It may be in '50s or '40s or '30s. Therefore, may I know, apart from recovering this money, what action you are going to take against the recalcitrant and defaulting company officials and whether you are going to put them behind bars?

SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH: If necessary, we will case against them for the recovery of the amounts. Criminal cases can also be filed against them.

Cost of generation of electricity

*331. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the average generation cost of electricity in the country and at what average cost it is being made available to the cultivators;

(b) at what cost it is supplied to the industrial sector; and

(c) whether Government propose to take any steps to ensure that electricity is made available to the cultivators at still lower rates?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) The cost of generation and supply as well as tariff for electricity varies from State to State. The average cost of generation and supply of power by different State Electricity Boards for the year ending 31-3-1986 has been estimated at 72.07 ps|unit. The average rate of realisation from the agricultural sector in the same year has been estimated at 20.62 ps|unit.

(b) A statement is laid on the Table of the House. (*See* below).

(c) No such proposal is under the consideration of Government.

Statement

Tariff for Industrial Sector as on 1-4-1986 *(inclusive of fuel cost adjustment and Electricity Duty).*

(Estimated average Rate in P/Kwh)

Name of the SEB	Small Industries 5 HP 10% L.F. (272 Kwh/Month)	Medium Industries 50 KW 30% L.F. (10950 Kwh/Month)	Large Industries 1000 KW 50% L.F. (36,5000 Kwh/Month)
1 2	3	4	5
1 Andhra Pradesh .	56·84	55·05	69·15
2 Assam . . .	57·00	57·00	55·19
3 Bihar . . .	112·00	110·00	97·28
4 Gujarat . . .	86·45	98·39	105·09
5 Haryana . . .	65·00	85·50	90·50
6 Himachal Pradesh .	44·00	59·00	57·00
7 Jammu & Kashmir .	22·70	22·70	20·40
8 Karnataka . . .	86·03	78·67	71·28
9 Kerala . . .	30·77	22·72	34·20
10 Madhya Pradesh (Urban)	58·00	72·70	84·12
11 Maharashtra . .	60·00	80·54	94·10

1	2	3	4	5
12	Orissa . . .	57·00	65·50	87·28
13	Punjab . . .	56·00	65·35	63·89
14	Rajasthan . . .	69·00	83·00	85·00
15	Tamil Nadu (Madras)	85 00	85.00	85.12
16	Uttar Pradesh . .	86.57	81.25	97.73
17	Delhi (DESU) .	78.00	78.00	113.73
18	Bombay (BEST) . .	151.00	151.54	125·66
19	Calcutta (CESC) .	80·00	85·16	103.50

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उस में प्रश्न के मूल में जो बात पूछी गयी थी दुर्भाग्य से उस का पूरा उल्लेख नहीं है। मैं यह जानना चाहता था कि किसानों को विभिन्न राज्यों में किस दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। जो स्टेटमेंट लगाया गया है उस में उद्योगों को जिस दर पर बिजली दी जा रही है उस का उल्लेख है, लेकिन किसानों को जिस दर पर दी जा रही है उसका उल्लेख नहीं है। क्या वह स्टेटमेंट भी हमें अलग से दिलवा दें।

महोदय, प्रश्न के भाग (ग) में जो उल्लेख किया गया है उसमें कहा गया है कि किसानों को बिजली कम दर पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहां की अर्थ-व्यवस्था पूरी किसानों पर निर्भर करती है। इस लिए कोई दो मत इसमें नहीं होने चाहिए कि किसानों को कम दर पर बिजली दिलाई जाए। विशेष कर मैं जानना चाहूंगा कि अब जब कि पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है तो क्या कम से कम ऐसे वर्षों में जब सूखा पड़ता है और कम से कम ऐसे क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ता है, वहां किसानों को कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब किसान बिजली का उपयोग नहीं करते तो उनसे अनावश्यक रूप से मीनिमम चार्जेज लिए जाते हैं, पीनल चार्जेज लिए जाते हैं, क्या उनके ऊपर पीनल चार्जेज न लगाए जाएं, शासन इस पर विचार करेगा?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जहां तक प्रश्न के पहले भाग की बात है, इसमें जो एनेक्सर दिया गया है उसमें हर प्रदेश में क्या दर बिजली की है, यह दी हुई है। माननीय सदस्य उसको देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं उसको सर्कुलेट कर दूंगी।

Mr. Chairman: How is it that some have got it and some have not? The questioner has not got it. Will you kindly make it available to him?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हर माननीय सदस्य के पास वह पहुंच जाएगा। इसमें दिया गया है कि हर राज्य में दर भिन्न भिन्न है कहीं थोड़ी है, कहीं अधिक है, पर औसत 20.62 पैसा प्रति यूनिट है।

जहां तक कृषि प्रधान देश की बात है, उसी को दृष्टि में रखते हुए हमारा प्रयास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां सूखा पड़ा है वहां भी प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई जाए।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त 69 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। हालांकि विद्युतीकरण पूरा नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की परिभाषा भी बदली जाए। गांवों में बिजली के खंभे लग जाने से ही विद्युतीकरण नहीं माना जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है। बिजली लगाने और उसको फैलाने में बिजली की लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि इसमें खर्चा काफी पड़ जाता है जिससे हम इस काम को जल्दी नहीं करवा पा रहे हैं।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारी राज्य सरकारों को इसके लिए सबसिडी देनी चाहिए और ज्यादातर राज्य उसमें सहायता नहीं दे रहे हैं, इसलिए जितना हम उसको बढ़ाना चाहते हैं उतना नहीं हो रहा है।

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, हमारे देश में बिजली की जेनरेशन प्रति यूनिट कास्ट अन्य देशों के मुकाबले में बहुत अधिक है। इसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विशेषकर हाइडल पावर की जेनरेशन कास्ट बहुत कम होती है, थर्मल पावर ज्यादा होती है। तो हाइडल पावर ज्यादा जेनरेट करके कम कीमत पर बिजली किसानों को दी जाए, इस पर सरकार क्या विचार करेगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं। 80 हजार मैगावाट कैपेसिटी अभी है जिसका पोटेंशल हम लोग टैप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे टिहरी आदि भी बन रही हैं। इन सारी चीजों के लिए जैसे जैसे धन मिलता जाएगा, इसके उत्पादन में औसत कास्ट कम हो, इस दिशा में बराबर कार्य हो रहा है।

श्री वसंत साठे : सभापति जी, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा 11 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। उसका मुख्य कारण यह है खेती के लिए जो सबसिडाइज्ड बिजली हम दे रहे हैं उसकी जेनरेशन कॉस्ट 72 पैसे है और 20 पैसे की दर से वह आप देंगे तो 50 पैसे प्रति यूनिट का जो घाटा होगा, उसे हिन्दुस्तान ही क्या दुनियां का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सहन नहीं कर सकता।

श्री चतुरानन मिश्र : इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट होती है उसका 2 परसेंट भी नहीं होता।

श्री वसंत साठे : एग्रीकल्चर में 20 परसेंट है। कहीं-कहीं बहुत ज्यादा है। हरियाणा वगैरह में ज्यादा है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Now, Papers to be Laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Payment of interim relief to public sector employees

*321. SHRI SHARAD YADAV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Central Government had on 1st January, 1986 sanctioned interim relief to the employees of public sector undertakings drawing salaries based on Industrial Dearness Allowance; and

(b) what are the names of the public sector industries under his Ministry where interim relief has been paid to the employees so far as also the names of such industries where the same has not yet been paid and what are the reasons for not providing interim relief to them and by when it is likely to be fully paid up?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) An